भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3546

10.08.2026 को उत्तर के लिए

ऋषिकुल्या नदी के मुहाने का संरक्षण और सुरक्षा उपाय

3546. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रहीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के संवेदनशील तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, विशेषकर ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के सामूहिक प्रजनन प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए किए गए विशिष्ट संरक्षण और निगरानी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीज़ेडएम) परियोजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गंजम तट की तटीय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर कोई तकनीकी अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इस परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बनाई गई रणनीतियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) ऑलिव रिडले कछुओं सहित वन्यजीवों का प्रबंधन और संरक्षण संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। ऑलिव रिडले कछुओं के अंडे देने के मौसम के दौरान, वन विभाग, संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय से, कछुओं के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय करता है, जिसमें तटीय उथले समुद्री जलक्षेत्रों में मशीनीकृत मत्स्यन पर मौसमी प्रतिबंध, गश्त, भारतीय तटरक्षक बल तथा मत्स्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निगरानी करना तथा कछुओं के अंडे देने वाले समुद्र तटों पर सार्वजनिक आवागमन को सीमित करना शामिल है, ताकि उन्हें न्यूनतम व्यवधान हो। इसके अतिरिक्त, जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने के साथ-साथ

अंडे देने की गतिविधियों, अंडों से शिशु कछुओं के बाहर आने तथा तट पर बहकर आने वाले कछुओं की नियमित निगरानी भी की जाती है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कछुओं की आवाजाही की पारिस्थितिकी और आवास उपयोग का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं, जिसमें फ़्लिपर टैगिंग और सैटेलाइट टेलीमेट्री शामिल है, जिससे ओलिव रिडले कछुओं के वैज्ञानिक संरक्षण और प्रबंधन में सहायता मिलती है।

(ख) ओडिशा राज्य में कार्यान्वित एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीज़ेडएम) परियोजना वर्ष 2020 में समाप्त हो गई।

(ग) मंत्रालय द्वारा गंजाम तट पर तटीय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है।

*****